

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजस्व लोक अदालत शिविर बिजौलियां कॅम्प गुढा
बईजलास श्री प्रवीण कुमार (RAS)

राजस्व प्रकरण संख्या: 30/2017

दायर तारीख 04.09.2017

1. छीतर पिता प्रभूलाल जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी उम्मेदपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा
2. मु0 घीसी बाई बेवा प्रभूलाल जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी उम्मेदपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा

.....वादीगण

बनाम

1. राजू पिता दुर्गालाल जाति बंजारा उम्र वयस्क निवासी चम्पापुर तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा राजस्थान।
2. मांगीलाल पिता मनोहरलाल जाति मीणा उम्र वयस्क निवासी कास्या तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा राजस्थान।

.....प्रतिवादीगण

उपस्थित:-

जगदीश चन्द्र धाकड अधिवक्ता वादी
मोहनलाल जोशी अधिवक्ता प्रतिवादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 183-188 रा0टि0एक्ट0

:-निर्णय:-

दिनांक 25.05.2018

वादपत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है वादी ने एक नियमित राजस्व वादपत्र अन्तर्गत धारा 183-188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरुद्ध प्रतिवादीगण इस न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा आंटी प0ह0 गुढा तह0 बिजौलियां की सरहद में आ0नं0 680/4 रकबा 7 बीघा भूमि वादी सं0 1 के पिता व वादीया सं0 2 के पति प्रभूलाल पिता मोडा धाकड के खातेदार अधिकार अधिपत्य की भूमि होकर कब्जे काश्त के उपयोग उपभोग में चली आ रही है। खातेदार प्रभूलाल की मृत्यु उपरान्त वादीगण के उपयोग उपभोग एवं कब्जे काश्त में चली आ रही है। लगान राज्य सरकार में जमा करवाते आ रहें हैं। प्रतिवादीगण का वादग्रस्त आराजीयात से कोई हक अधिकार नहीं है। वादीगण ने वादग्रस्त आराजीयात का कोई विक्रय हस्तान्तरण नहीं किया है। उसके बावजूद भी प्रतिवादीगण वादग्रस्त आराजीयात पर फसल काश्त करते समय लडाई झगडा व मारपीट करने पर उतारु रहते हैं। प्रतिवादीगण काफी प्रभावशाली व्यक्ति है वादी सं0 1 के पिता व प्रतिवादी सं0 2 के पति प्रभूलाल की मृत्यु होने से प्रतिवादीगण के होसले बुलन्द हो गये। वादग्रस्त कुलिया भूमि पर प्रतिवादीगण ने अवैध कब्जा कर लिया। जून 2017 मे काश्त करने गये तो वादीगण को वादग्रस्त आराजीयात पर काश्त नहीं करने दी व झगडा करने पर उतारु हो गये एवं धमकी दी की तुम्हे काश्त नहीं करने देंगे। इस कारण वादीगण की वादग्रस्त आराजीयात पर स्वयं की खान का पत्थर काटकर पत्थर का स्टॉक लगा दिया है कृषि भूमि के स्वरुप को नष्ट कर दिया है। साथ ही वादग्रस्त आराजीयात से प्रतिवादीगण को बेदखल किया जाकर वादीगण को सिपूद किया जावे। प्रतिवादीगण प्रभावशाली व्यक्ति है पूनः कब्जा कर सकते है इस कारण स्थाई निषेधाज्ञा बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण प्राप्त करने का अधिकारी है कि वादग्रस्त आराजीयात से प्रतिवादीगण को बेदखल करने के उपरान्त पूनः वादग्रस्त आराजीयात पर कब्जा नहीं करे साथ ही कब्जा प्राप्ति दिनांक तक लगान का 50 गुणा मुआवजा बतौर क्षतिपूर्ति प्रतिवादीगण से वादीगण को दिलाई जावे।

यह
उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियां (भीलवाडा)

वादपत्र दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर प्रतिवादीगण की तलवी जरिये समन मय नकल वादपत्र भेज करवाई गई।

प्रतिवादी सं० 1 की और से वकील श्री मोहनलाल जोशी ने अधिकार पत्र मय जवाब प्रस्तुत किया। प्रतिवादी सं० 2 की और से श्री ओमप्रकाश शर्मा ने अंडर टेकिंग लिया। किन्तु तत्पश्चात अधिकार पत्र व जवाब प्रस्तुत नहीं करने से एकपक्षिय कार्यवाही के आदेश पारित किये गये।

जवाब में अंकित किया कि वादपत्र गलत तथ्यों पर प्रस्तुत किया गया है वादपत्र की चरण सं० 1 में अंकित राजस्व भूमि पर खातेदार प्रभूलाल पिता मोडा धाकड कभी कब्जा नहीं रहा हैं प्रभूलाल धाकड की मृत्यु के पश्चात वादीगण का भी उक्त राजस्व भूमि पर कभी कब्जा नहीं रहा है। केवल मात्र राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि पर वादीगणों का कब्जा नहीं रहा है। प्रतिवादीगण उक्त कृषि भूमि पर काफी वर्षों से पिता के जीवन काल से काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहे हैं जिस पर प्रतिवादीगण का कब्जा नहीं रहा है ऐसी स्थिति में जब प्रतिवादीगण ने वादीगण के कब्जे काशत भूमि में कभी अतिक्रमण ही नहीं किया है तो इसे विधी विरुद्ध कब्जा नहीं कहा जा सकता। प्रतिवादीगण का उक्त वादग्रस्त भूमि पर काफी वर्षों से कब्जा चला आ रहा है ऐसी स्थिति में प्रतिवादीगण द्वारा वादीगणों के उपयोग उपभोग में दखलन्दाजी किये जाने का कोई विधीक आधार शेष नहीं रहता है। जिससे वादीगण को वादकारण प्राप्त नहीं होता है एवं स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है वादीगण का वादपत्र पोषणीय नहीं है। वादीगण को उक्त आराजीयात पर विधीक रूप से कभी काबिज नहीं किया गया था। ऐसी स्थिति में प्रतिवादीगण को बेदखल कर वादीगण को कब्जा सिपूर्द करने का कोई विधीक आधार शेष नहीं रहता है एवं वादीगण किसी तरह के मुआवजे की राशि प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। वादीगण ने केवल राजस्व रिकार्ड के आधार पर गलत तथ्यों को आधार बनाकर वादपत्र पेश किया जो खारिज फरमाया जावे।

वादी ने वादपत्र के साथ नकल जमाबंदी सम्वत् 2070 से 2073 खाते की नकल पेश की है।

वादपत्र व प्रतिवाद पत्र के आधार पर निम्न तनकियात कायम की गई।

- 1 आया कि वादग्रस्त आराजी नं० 680/4 रकबा 7 बीघा भूमि वादीगण की खातेदारी अधिकार अधिपतय की कृषि भूमि है जिस पर प्रतिवादीगण ने बिना विधीक अधिकार के कब्जा कर लिया है जो बेदखल किया जाने योग्य होकर वादीगण कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है।जिम्मेवादीगण
- 2 आया कि वादग्रस्त भूमि वादीगण की खातेदारी अधिकार अधिपत्य की भूमि है प्रतिवादीगण का वादग्रस्त भूमि में कोई हक अधिकार स्वामित्व नहीं होकर वादीगण स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है।जिम्मेवादीगण
- 3 आया कि वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादीगण वर्षों से काबिज है और प्रतिवादीगण के उपयोग उपभोग में है। इस कारण वादीगण कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है।जिम्मे प्रतिवादीगण

प्रतिवादी द्वारा जवाब के अतिरिक्त किसी प्रकार के मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने से तनकीवार विवेचन नहीं किया जा रहा है।

वादीगण ने मौखिक किसी प्रकार की साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने से शहादत वादी बंद की गई।

प्रतिवादीगण ने मौखिक किसी प्रकार की साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने से शहादत

उप उपर अधिकारी
विजालियाँ (मौलवांजा)

बहस उभयपक्षकरान सूनी गई।

बहस के दौरान अधिवक्ता वादी ने वादपत्र में अंकित तथ्यों का विस्तार से जिक्र करते हुये वादपत्र को डिक्री किये जाने की मांग की।

बहस के दौरान अधिवक्ता प्रतिवादी ने जवाब में अंकित तथ्यों का विस्तार से जिक्र करते हुये वादपत्र को सव्य खारिज किये जाने की मांग की।

प्रकरण को मेरिट पर गुणावगुण के आधार पर शिविर में निस्तारण करने हेतु सहमती व्यक्त की।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया बहस उभयपक्षकारान अधिवक्तागण पर मनन किया।

पत्रावली में संलग्न जमाबंदी ग्राम आटी सम्वत् 2070 से 73 के खाता संख्या 98 पर अंकित खातेदार के नाम आ0नं0 680/4 रकबा 7 बीघा भूमि वादीगण के नाम दर्ज रिकार्ड है। वादीगण का वादग्रस्त भूमि पर कब्जा नहीं होने से कब्जा प्राप्ति हेतु धारा 183 के तहत वादपत्र प्रस्तुत किया है। प्रतिवादी स्वयं ने जवाब में वादी के नाम पर दर्ज भूमि पर प्रतिवादी का कब्जा होना स्वीकार किया है। प्रतिवादीगण ने जवाब के अलावा किसी प्रकार की साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। वादीगण ने स्वयं ने अपने वादपत्र में कब्जा प्रतिवादी का होना लिखा है तथा कब्जा हटाये जाने की मांग की है। प्रतिवादी ने कब्जा स्वीकार करते हुये यह तथ्य अंकित किया कि वर्षों पूर्व से ही प्रतिवादी काबिज हो काश्त करते आ रहे हैं। किन्तु प्रतिवादी ने इस तथ्य को साबित कराने हेतु किसी प्रकार की दस्तावेजी/मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। केवल जवाब में तथ्य अंकित कर देने मात्र से बिना प्रमाणित किये माना नहीं जा सकता। प्रस्तुत वादपत्र वादी डिक्री योग्य है।

अतः वादपत्र वादी अन्तर्गत धारा 183-188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर ग्राम आंटी स्थित आ0नं0 680/4 रकबा 7 बीघा भूमि पर प्रतिवादीगण का अवैध कब्जा हटाया जाकर जमाबंदी में दर्ज खातेदार को कब्जा सम्भलाने का आदेश तहसीलदार बिजौलियां को दिया जाता है। साथ ही प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जाता है कि रिकार्डेड खातेदार के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी न तो स्वयं करे न ही अन्य से करावे। खर्चा अपना-अपना वहन करे। डिक्री मुर्तिब हो।

आदेश आज दिनांक 25.05.2018 को लिखवाया जाकर मजमे आम गुढा केम्प कोर्ट न्यायालय पर सुनाया गया।



25/05/18
उपसपड अधिकारी
बिजौलियां
(केम्प गुढा)